

विचार बिन्दु

महान विचार ही कार्य रूप में परिणत होकर महान कार्य बनते हैं। -विनोबा

सरकार के दो साल, जनता का हाल बेहाल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसमें प्रत्येक विभाग की उपलब्धियों के आंकड़े दिए गए और बताया गया कि विभिन्न विभागों ने राजस्थान को देश में प्रथम स्थान दिलाया है।

इस लेख का उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्मेलन में दिए गए आंकड़ों को चुनौती देना नहीं है, बल्कि केवल यह कि आम जनता के जीवन पर इन दो सालों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है एवं क्या उसका जीवन पहले से बेहतर हुआ है? क्या उसके साथ अन्याय पहले से कम हुआ है? क्या सरकार अपने वे सब काम भलीभांति कर रही है जिससे आम जनता का जीवन प्रभावित होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, अपराधों पर नियंत्रण आदि।

जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, अर्थशास्त्री एक ही प्रकार के आंकड़ों से अलग-अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण अपने-अपने दृष्टिकोण से करता है और निष्कर्ष भी उसी अनुसार निकालता है। आंकड़ों की जादूगारी करने में आर्थिक विशेषज्ञों को महारत हासिल है। राजनीतिक दल भी इनका उपयोग अपने हित अनुसार करते हैं।

यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश है। यहां की जीडीपी वृद्धि की दर अन्य सभी देशों से कहीं अधिक है। भारत की कुल जीडीपी पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। लेकिन यदि हम इसके उलट, यह देखें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देश के नागरिकों की आय में असमानता कितनी है, उन्हें मिलने वाली मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता की स्थिति क्या है, एवं प्रभावार की क्या स्थिति है, तो हम यह पाएंगे कि इन सब पैमानों पर भारत विश्व में बहुत नीचे के पायदान पर खड़ा है। इन मापदंडों पर भारत कई अग्रणी देशों से भी पीछे है।

अंग्रेजी में कहावत है, " Test of the pudding is in eating it"। सरकार के परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखें तो यह कहेंगे कि योजना पर कितना खर्च हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उससे राज्य की जनता कैसे प्रभावित हुई? आइए, हम कुछ क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का विश्लेषण, इस दृष्टि से करने का प्रयास करें।

कुछ ही दिनों पहले मीडिया में प्रमुखता से यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि राज्य के केवल 9 जिलों में ही 300 से अधिक शिक्षक ऐसे विद्यालयों में पद स्थापित हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि लगभग 2 करोड़ रूपया महीना व्यर्थ हो रहा है। यह राशि उस जनता से एकत्रित की जाती है जो पूरी मेहनत करके जैसे-जैसे अपने लिए दो जून रोटी का जुगाड़ करती है। दूसरी ओर, अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। क्या इसे शिक्षा विभाग की असफलता नहीं माना जाएगा? आजकल सारे आंकड़ों का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है और केवल एक क्लिक पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को पूरे प्रदेश के सारे विद्यालयों का पूरा खाका उपलब्ध हो जाता है। वहां किसी अधिकारी को इतने समय तक यह क्यों नहीं पता लग पाया कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक बिना छात्रों के वेतन प्राप्त कर रहे हैं? जिस राज्य में पैसे की कमी को बहाने के रूप में काम में लिया जाता है, वहां दो करोड़ रुपए प्रति माह अर्थात लगभग 25 करोड़ रूपया साल का ऐसे लोगों को वेतन के रूप में दे देना जिनके पास कोई काम नहीं है, उसे राज्य की शासन व्यवस्था को अच्छा कैसे माना जा सकता है?

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति वैसे ही बड़ी कमजोर है और उस पर सरकारी विद्यालयों का यह हाल किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। इसके लिए शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से लेकर राज्य स्तर के अधिकारी और शिक्षा मंत्री तक को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे?

भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसी की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलाई जा रही है। यह दावा किया जाता है कि सभी गरीब परिवारों को इसके अंतर्गत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में लाखों रुपए तक का मुफ्त में इलाज कवस्थ उपलब्ध है। जिस प्रकार के समाचार प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं उससे तो यही लगता है कि यह योजना केवल कागजी सिद्ध हो रही है और वास्तविक रूप से वंचित और गरीब वर्ग को अब भी किसी न किसी कागज के अभाव में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध नहीं हो रहा है। कोई मरीज यदि एक इलाज के लिए भर्ती हो और उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार का इलाज करना पड़ जाए तो अस्पताल उससे पैसा वसूल करते हैं। सरकार के इस दावे पर विश्वास करके कि सबको अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है, यदि कोई नागरिक इलाज कराने किसी अस्पताल में पहुंच जाए तो वहां जाकर के उसके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होने के कारण उसे इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है।

कुछ ही दिनों पहले मीडिया में प्रमुखता से यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि राज्य के केवल 9 जिलों में ही 300 से अधिक शिक्षक ऐसे विद्यालयों में पद स्थापित हैं जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि लगभग 2 करोड़ रूपया महीना व्यर्थ हो रहा है। यह राशि उस जनता से एकत्रित की जाती है जो पूरी मेहनत करके जैसे-जैसे अपने लिए दो जून रोटी का जुगाड़ करती है। दूसरी ओर, अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं ।

इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार होगा? सरकारी व्यवस्थाओं में घोर लापरवाही और मॉनिटरिंग के अभाव में राजस्थान के नागरिक असमय काल कवलित हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं की निरंतर पुनरावृत्ति राज्य शासन की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की पोल खोलती है।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, बिना मॉनिटरिंग के योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार ने कुछ वर्षों पूर्व एक योजना MLA-LAD प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत विधायकों को प्रतिवर्ष एक निर्धारित बजट आवंटित होता था, जिसे वे स्थानीय आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा से कोई भी काम स्वीकृत कर सकते थे। कार्य किस विभाग या एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, यह तय करने का अधिकार भी संबंधित विधायक को दिया गया था। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 40 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान था, जो अब बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गया है। इस का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय स्तर के अन्यावश्यक उपयोगी काम संबंधित विधायक इस राशि से करवा सकें।

कुछ समय पहले तक सुना जाता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कामों को लिए एजेंसी तय करते समय विधायक/ सांसद कुछ धनराशि संबंधित विभाग के अधिकारियों से ले लिया करते थे, किंतु राजस्थान में जो हाल ही में स्थिति सामने आई है वह तो और भी चिंताजनक और भयावह है। एक रिपोर्टर ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो खीवसर के विधायक ढांगा ने तो कार्य पर खर्च होने वाली राशि का 30 से 40% तक लेने की मांग है। कल्पना ही की जा सकती है कि जिस काम की स्वीकृति के लिए विधायक 40% राशि रिखत में लेगा तो, उस काम पर वास्तव में कितना खर्च होगा? ऐसे ही रिखत लेने की बात एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के विधायक ने भी की। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे करारए गए काम अत्यंत घटिया स्तर के होंगे जो शीघ्र ही बेकार हो जाएंगे। सड़कें टूट जायेंगी, और विद्यालय की छर ध्वस्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने पद संभालते ही कहा था कि "न मैं खाऊंगा, ना खाने दूंगा"। भाजपा विधायक की इस हरकत पर अब प्रधानमंत्री क्या कार्यवाही करते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।

आशा है, तत्काल इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्काहित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात यह है कि मीडिया में जिन विधायकों को एमएलए फंड से स्वीकृति के लिए पैसे की मांग करते हुए रिर्कांड पर पकड़ा गया, उनमें भाजपा के अतिरिक्त एक कांग्रेस का और एक निर्दलीय विधायक भी हैं।

नशे की स्थिति यह है कि पूरा शहर ही नशे के जाल में झकड़ा हुआ नजर आता है। युवा, विशेष कर नाबालिग बच्चे इन ड्रग्स का शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की राजधानी जयपुर में यह विद्यालयों के पास और विभिन्न स्थानों पर घडवले नशे बेची जा रही है। जब किसी समाचार पत्र का एक रिपोर्टर यह पता कर सकता है कि कहाँ किस प्रकार के ड्रग्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो वहां के थानेदार या उच्च पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होगी? जानकारी होगी अवश्य, किंतु शायद लालच में वे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं।

शहर की सफाई, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था में गत 2 वर्ष में कोई सुधार नहीं हुआ है, अपितु स्थिति पहले से और खराब हो गई है। राज्य की राजधानी जयपुर में विभिन्न बस्‍तियों में गंदगी के ढेर प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। बेतरतीब पार्किंग यथावत है और सड़कें अनधिकृत पार्किंग से टास्त हैं। जब इंदौर गंदगी से मुक्त हो सकता है, तो जयपुर क्यों नहीं? क्या यह नहीं हो सकता कि शहर से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी चाहे वे पी डब्लू डी, पी एच ई डी, नगर निगम, राजस्व, विद्युत, ट्रैफिक विभाग के हों, सभी नगर निगम के अधीन होने चाहिए। उन पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण नगर निगम का ही होना चाहिए। तब, समन्वय की समस्या नहीं रहेगी।

यदि वास्तव में मुख्यमंत्री को जनता का विश्वास प्राप्त करना है और सुशासन वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज कराना है तो उन्हें अपने कार्यकाल के शेष 3 वर्ष में केवल आंकड़ों पर ध्यान देने के बजाय ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे धरातल पर आमजन को उसका वास्तविक लाभ मिले। इसका आकलन करने हेतु स्वतंत्र, निष्पक्ष व्यक्तियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए।

जब सरकार अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है तो आम जनता यही अपेक्षा करती है कि उसके सारे काम सरकार में बिना परेशानी के हों, जो पैसा उससे वसूल किया जाता है उसका शत प्रतिशत सदुपयोग किया जाए और जो इसमें बाधक बने उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जनता को सूचित किया जाए। ऐसा करने में प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना एवं दल के कार्यकर्ताओं का विरोध भी मुख्यमंत्री को झेलना पड़ सकता है, किंतु जनता के हित का यही रास्ता है जो उन्हें लोकप्रियता प्रदान करेगा और साथ ही जनता को राहत भी।

मुख्यमंत्री का जन्म दिवस भी संयोग से 15 दिसंबर को है, अत: उन्हें जन्मदिन के बधाई के साथ ही उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा करने पर बधाई एवं उनके शेष कार्यकाल के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं। मेरी यह कामना है कि एक वर्ष बाद जब मैं ऐसा ही संपादकीय लिखू तो शीर्षक ऐसा हो, "सरकार के तीन साल, आम जन खुश हात"।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

सुशासन की सेहत : मजबूत होता राजस्थान का सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र



गजेन्द्र सिंह खीवसर

स्वास्थ्य तंत्र सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का सबसे प्रामाणिक पैमाना होता है। राज्य सरकार का विगत 2 वर्षों में यह प्रयास रहा है कि गरीब परिवार बिना आर्थिक चिंता के इलाज पा सके, एक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले और गंभीर बीमारी भी परिवार को कर्ज के दलदल में न धकेले।

राजस्थान ने गत दो वर्षों में इसी कसीटी पर अपने स्वास्थ्य तंत्र को नए सिरे से सुदृढ़ करने का कार्य किया है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट मार्गदर्शन, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और परिणामोन्मुख प्रशासनिक संस्कृति का प्रत्यक्ष परिणाम

है। मुख्यमंत्री का आरंभ से ही यह दृष्टिकोण रहा है कि स्वास्थ्य योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार ने नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, आयुष्मान आरोग्य, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा हर स्तर पर टोस, मापनीय और जनजीवन को सीधे प्रभावित करने वाले कदम उठाए हैं।

राजस्थान आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहाँ नि:शुल्क दवा योजना केवल सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन का उदाहरण बन चुकी है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत लगभग 1०34 करोड़ रुपये से अधिक की दवाइयों की आपूर्ति कर 1० करोड़ से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। मेडिकल कॉलेज स्तर से लेकर उप-स्वास्थ्य केंद्रों तक आवश्यक दवाएं, सर्जिकल और सुचर सामग्री सुनिश्चित की गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अंतर्गत 774 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 30 करोड़ जांचें की गईं, जिससे 8 करोड़ से अधिक मरीजों को सीधा लाभ मिला। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को न केवल आर्थिक राहत मिली, बल्कि समय पर जांच और इलाज संभव हो सका।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा विस्तार कर इसमें 132 नए पैकेज जोड़े गए। इसके अंतर्गत 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6860 करोड़ रुपये से अधिक की कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह योजना अब केवल राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि इन-बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य राज्यों के लाभार्थियों को भी राजस्थान में उपचार का लाभ दे रही है। यह न केवल योजना की मजबूती दर्शाता है, बल्कि राजस्थान को विश्वसनीय स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। प्रदेश में 7 उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पताल में उन्नयन, 61 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उप जिला अस्पतालों में उन्नयन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को भौगोलिक दृष्टि से सुलभ बनाने के लिए 49 नए उप-स्वास्थ्य केंद्र, 6 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 379 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रारंभ किए गए।

डायलिसिस, वेंटिलेटर, सोनोग्राफी और आईसीयू सुविधाओं के विस्तार के तहत राज्य के 195 चिकित्सा संस्थानों में 390 डायलिसिस मशीनें, 186 वेंटिलेटर और 51 सोनोग्राफी मशीनें स्थापित की गईं। इससे गंभीर रोगियों को जिला स्तर पर ही बेहतर उपचार उपलब्ध हो सका है। आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 53 पुराने 108 एंबुलेंस

नियमों की अनदेखी पर 13 बाल वाहिनियों के चालान काटे, कई वाहन जब््त

दो बाल वाहिनी, एक स्कूल वेन व 10 वाहनों को शर्तों के उल्लंघन करने पर जब््त किया

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस ने नियमों की अनदेखी पर 13 बाल वाहिनियों के चालान काटे। जांच के दौरान कई वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना, और वैध दस्तावेजों की अनुपस्थिति जैसे गंभीर उल्लंघन पाए गए।

पुलिस ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के तत्वाधान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपुतली-बहेरडो के निर्देशन व तालुका विधिक सेवा सेवा समिति विराटनगर अध्यक्ष कुमार मोहन, सीबीईओ विराटनगर रामेश्वर जाट, आरटीओ भारतेंदु, विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल संयुक्त टीम का गठन कर विराटनगर थाना क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में उपयोग में ली जा रही बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद विराटनगर थाना क्षेत्र में स्कूल वाहनों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई की गई। बाल वाहिनियों पर की गई कार्यवाही में बिना फिटनेस, बिना कैमरे के संचालित जांच के दौरान



विराटनगर थाना पुलिस ने नियमों की अनदेखी पर बाल वाहिनियों को जब््त किया।

लगभग 30 बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया गया। वहीं 13 बाल वाहिनियों का चालान किया गया, 1 वाहन फिटनेस नहीं होने के कारण जब्त किया गया, 1 वाहन की भौतिक स्थिति खराब होने के कारण जब्त किया गया एवं 10 वाहनों को बिना कैमरे व

दो दशक से मरम्मत को तरस रही है सड़क सांभर में सिंधी व गोला बाजार की सड़क करीब दो दशक से मरम्मत को तरस रही है

सांभरझील, (निसं)। सांभर के दो महत्त्वपूर्ण सिंधी व गोला बाजार की सड़क करीब दो दशक से मरम्मत को तरस रही है। इन दोनों बाजारों की अनदेखी की मुख्य वजह आमजन की समझ से परे है। सिंधी बाजार की सड़क की तो जगह-जगह से कंक्रीट तक बिखर चुकी है। दो पहिया वाहन तो दूर पैदल चलना भी कठिन हो रहा है।

जानकारी के अनुसार विगत दो

दशकों में करोड़ों रुपया नगर की सड़कों पर खर्च किया जा चुका है इनमें से कुछ मार्गों की सड़कें तो ऐसी है जो पहले से ही ठीक हावत में थी। लेकिन उखाड़ कर दोबारा बनाई गई जिसका कोई औचित्य नहीं था। इन सड़कों को सुधारने के लिए न तो कोई प्लान तैयार किया गया और न ही जनप्रतिनिधियों ने इसमें इंटरैट लिया। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है। जगह-

■ बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, कीचड़ जमा होने से गोला बाजार के हालात भी खराब हो जाते हैं

जगह कीचड़ जमा होने से गोला बाजार के हालात भी बदतर हो जाते हैं। इसी

प्रकार पृथ्वीराज चौहान सर्किल से लेकर साल्ट फाटक तक सड़क भी अनेक जगह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। पिछले साल पर्यटन महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले इन गड्ढों को भरवारा गया था फिर उसके बाद दोबारा सुध नहीं ली।

पुरानी देवयानी रोड छोटा बाजार में काफी दूरी तक पेयजल लाइन के लिए खोदी गई सड़क आज तक नहीं

बन सकी है। छोटा बाजार से बड़ा बाजार तक की सड़क की सुध केवल वर्ष में एक बार यानी धूलंडी के अवसर पर ली जाती है वह भी केवल गड्ढों को भरने तक सीमित रहती है। इन मुद्दों को जिम्मेदार पाएँद बोर्ड की बैठक में उठाना तक भूल जाते हैं। यहां की बोर्ड की मीटिंग भी अब तक जितनी बार हुई है करीब करीब औपचारिकता पूर्ण सिद्ध हुई है।

राशिफल मंगलवार 16 दिसम्बर, 2025					
	मेघ		सिंह		धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। शुभ कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
	वृष		कन्या		मकर
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	परिवार में व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
	मिथुन		तुला		कुंभ
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।	परिवार में व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
	कर्क		वृश्चिक		मीन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	आय में वृद्धि होगी। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।